Title: Demand to take immediate steps to meet the situation arising due to Supreme Court's order regarding closing of diesel buses in Delhi.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे दिल्ली के लाखों लोग परेशान होने वाले हैं। एक अप्रैल, 2001 से दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी बसें बंद कर दी जाएंगी। दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार है, उसने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आज उनके पास मात्र 130 बसें हैं जबकि दिल्ली में लोगों को लाने-ले जाने के लिए लगभग 10,000 बसों की आवश्यकता है। 1998 से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस दिशा में चेतावनी दी है कि वे कदम उठाएं। उसके लिए उन्होंने बजट भी रखा लेकिन कोई बजट खर्च नहीं किया। दिल्ली में जो लोग अपने काम-धंधों पर जाने वाले हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग, यहां तक कि छात्र भी स्कूलों में नहीं जा सकेंगे जिससे उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ऐसी सरकार को, जो एक अप्रैल के बाद पूरी दिल्ली को अंधेरे में छोड़ देगी, सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक अप्रैल से पूरी दिल्ली में जो स्थिति आ रही है, यातायात की दृटि से हालत खराब होने वाली है, उसके सुधार के लिए कोई न कोई सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में जरूर कुछ कहें क्योंकि दिल्ली की बहुत विाम समस्या का सवाल है। लोग अपने काम-धंधों पर नहीं जा पाएंगे। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। इस पर विशे ध्यान दिया जाना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Sahib Singh Verma, Shri Madan Lal Khurana, Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Vijay Goel may all associate themselves with this issue.

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यदि सरकार यह कहती कि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो आशा की कोई किरण दिखाई देती। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल 500-600 बसें करवा सकती हूं जबकि आवश्यकता 10,000 बसों की है। स्कूल खुलने के बाद सारी दिल्ली को 10,000 बसें चाहिए जबकि केवल 300-400 बसें ही हैं। दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। लोग दफ्तरों में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सरकार को कुछ करना चाहिए।